## . श्रम विभाग

## दिनांक 23 ग्रप्नैल, 1985

सं भी. किरीदाबाद/46-85/17865. चंदूकि हरियाणा के राज्यपाल की राम है कि मैं राज्यहंजीनियरिय पुण्ड फार्जडरी, प्लाट नं 68, सैक्टर-24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री लेहरी खान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके ्वाद तिक्षित मामने में हं भीकोणिक विवाद है;

भीर व हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं:

इसिल्सन, भोद्योगिक विवाद सिवित्यम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के सण्ड (ग) द्वारा प्रवान की गई शिव्यों का प्रयोगित हुने हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 5415-3-अम/68/15254; दिनोक 20 जून, 1968, के साथ चूए प्रविद्वचना सं 11495-जी-अम-88-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उत्तर अधिनयक की द्वारा 7 के व गिंठत अस न्यायालय, फरीदावाद, की विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीने लिखा मामसा भायनिर्णय के लिदिंड करते हैं जो कि उन्तर प्रवन्धकों तथा अभिक की बीच या तो विवादग्रस्त मामसा है या विवाद से सुसंगत अपवा सम्बन्धित नीने :—

को लेहरी खान की सेवाओं का समापन त्यायोजित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहर का हक्यार है?

हैं। महाना | 216-84 | 17872 -- चूंकि द्दियाणा के राज्यपान की राय है कि चीछ एडिमिनस्ट्रेंटर हिंदा महाराज्य हैं। कि चीछ एडिमिनस्ट्रेंटर हिंदा महाराज्य हैं। कि चीछ एडिमिनस्ट्रेंटर हिंदा महाराज्य की स्थान कि चार कि चीछ एडिमिनस्ट्रेंटर हिंदा महाराज्य की स्थान की कि चीछ की कि चीछ की कि चीछ की कि चीछ कि चीछ

, ह हिरियाणा के राज्यनान विवाद को न्यायनियंग हेतू निविध्ट करना वोखनीय समझते हैं ;

हारा अभिनिक विवाद अधिनियम, 1947, की झारा 10 की जपसारा (1) के सक्त (व) सारा अक्षम की वह विवादी मा अवीम (, द्रियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी प्रक्षित्वना सं. 3(44) 84-3-यम, दिनांक 18 अप्रैस, 1984, कारा अनियम को धारा 7 के अबीन गठित श्रम न्यायालय, अन्वाला को विवादशस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा पानला व्य हेतु निविष्ट करते हैं, जो कि उनत प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादशस्त मामला है। या विवाद से सुसंगत मिनियंत मामला है:---

ा श्री कृष्ण चन्द्र की सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ?यदि नहीं, तो वह किस राहत का इकतार है ? वि. श्रिक्तलां 114-84/17879.--चूंकि हरियामा के राज्यात को राज है कि (1) मुख्य प्रवासक हरियामा प्राप्त के अंगार्श हरियामा, वंश्वाह, (2) नुष्टर माने गर्भाह रियामा स्रवेत डिजन गर्नेट भ्रायोटी पंच मूला, हरियामा के क्रिया तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित नामने में कोई भी योगिक विश्वाद है;

र पूरि हरियांगा के राज्यराल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिश्ट करना वोखनीय समझते हैं;

इतिए, घर, प्रौद्योगिक विवाद प्रविनियम, 1947, को वारा 10 की उपवारा (1) के खण्ड (ग) हारा प्रदान की वर्ष विवाद करते हुये हुरियामा के राज्यवाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 (44) 84-3-अस, दिलांक 18 अप्रैस, वृद्ध जनत अभिनियम की भारा 7 के अभीन गठित अस न्यायालय, प्रान्याला, को विवादशस्त या उससे पुरंपत का वृद्ध के स्ति विका मामला न्याय निर्मय के लिए तिर्दिष्ट करते हैं जो कि उनत प्रकाशनों तथा अभिक के बीच या तो विवादशस्त मामका है। सुसंपत अथवा सम्बन्धित भामला है:—

या थी अर्र्या की सेवाओं का समापन त्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस शहत का सकरार है है

्षी. विश्विम्बालां/39-85/17886,—चूंकि हरियांणा के राज्यपास की राम है कि मैं, वड़ा गांव कोमांपरेटिव केडिट ,सोसाईटी लि॰ बड़ा गांव, सहसील नरायणगढ़, जिला श्रम्बाला के श्रीमक श्री नत्यु पाम तथा उसके प्रवत्यकों के पड़व , बाद जिब्रित मामसे में कोई सीदोगिक विवाद हैं;

भीर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिजय हेतु निविध्ट करना बोछनीय समझते हैं;

इस लिए, श्रव, श्रीबोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के ख्र (ग) द्वारा प्रदान की विव शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इ सके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-श्रम, रनांक 18 श्रप्रेल, 1984 द्वारा उस्त प्रधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, श्रम्बाल, को विवादशस्त र उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा पामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उस्त अबन्धकों तथा श्रमिक नेविच या को विवादशस्त पामला है या विवाद से सुसंगत अयवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री नत्यु राम की क्षेत्राओं का समापन न्यायोजित तथा ठीक है ? यदि वहीं, सी वह किस त का हकदार है ?

सं. भ्रो.वि./मम्बालां/229-84/17892.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राम है कि ) पेरिवाहन भ्रायुक्त हरियाणा, चण्डीसड़ (2) जनरल मैतेजर, हरियाणा रोडवेज, यमुनानगर, के श्रमिक श्री सभी चन्द तथा उसनेतन्त्रकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भौद्योगिक विवाद है;

भीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हैतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं
इसलिए, भव, भौधोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग)रा प्रदान की गई
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 3(44)84-3 श्रम शंक , 18 अप्रैल,
1984, द्वारा उनत अधिनियम की धारा 7 के प्रयोग गठित श्रम न्यायालय, श्रम्याला, को विवादग्रस्त या उससे सन्त नीचे लिखा
भौमता न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो शि उनत प्रवस्त्रकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त म है या विवाद
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

तमा भी अभी चन्य की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस चा ह्रकदार है ?

सं. थो. वि./मध्याला/226-84/17899.--चूंकि सूरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ) सचिव, हरियाणा राज्य विजयों कोई, वासीए (2) कार्यकार प्रतिस्तात (प्रतिस्त हरीजन), हरियाणा राज्य विजनी के जीर, के व्यक्तिक श्री सोहन सिंह तथा उनके प्रवस्थकों के महत्र इसमें इसके बाद निश्चित मामले में कोई मीसोगिस निवा

ंभीर चूंकि हरियाणा के राज्यनाल विवाद को न्यायनिर्गय हेनू निर्दिष्ट करना नांछनीय समझते हैं 📜

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद प्रजितियम, 1947, की घारा 10 की उपनारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की त्यों का प्रयोग करते हुए हरियामा के राज्यवाल इस है द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 3(44)84-3श्रम, दिनांक 18 प्रप्रैल, 198 उन्हें अधिनियम की घारा 7 के अभीन गाँठत श्रम न्यायालय, अन्बाला, का विवाद प्रस्त या उसने सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याभ लिये निद्धित्य करते हैं जो कि उनत प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत भयवा समामला है :---

क्या श्री सोहन सिंह की से अभी का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकद

सं. मो.वि./पानीनतं 25-35/17906.--चूंकि हरियाणा के राज्यशास की राव है कि में. ज्योति इंस् सजोती रोड, उम्र बेड़ी, पानोता, के अनिक श्री आजाद तथा उसके प्रवन्तकों के मध्य इसके वास निर्मित्र को विद्योगीन निनाद है ;

... . . . . . श्रोर . चूंकि द्रुरियाणा के ट्राञ्चनाल विकास की स्थापतिर्गेश हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, ग्रन, ग्रीवोगिक विनाद स्रिजिन्नन, 1947, की धारा 10की उनवारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रद गिक्तमों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यनाल इसके द्वारा सरकारी प्रिजित्वना सं. 3(44)84-3भन, दिनांक . .1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के मधीन गठित थम न्यायालय, प्रम्याता, को विनादग्रस्त या उससे संबंधित नी मायला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिस के बीच या तो विनादग्रस्त मामल विवाद सुसंगद मयना संबंधित गामला है :—

क्या क्षी आज़ाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का

जै० पी० रतन, उप सचिव, हरियाणा सरका श्रम विभाग।